Benefits of concessional power in rural areas

994. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that benefits of concessional power in rural areas is confined to a limited number of people;

(b) whether it is also a fact that Government propose to carry out a survey in this regard and if so, by what time;

(c) whether it is also a fact that Government propose to rationalise the supply of power at concessional rates in rural areas; and

(d) if so, by when and if not, reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN *THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V.* RANGAYYA NAIDU): (a) and (b) No, Sir. About 84 per cent of the villages in the country have already been electrified, while about 28 per cent of the total sale of electricity by SEBs is accounted for by the agricultural sector, which fetches an average realisation of only 12.58 P/kwh.

(c) and (d) The tariff for supply of electricity to the different sectors of consumers is fixed by the SEBs/State Govts. concerned. The Power Ministers' Conference held in January, 1993 had adopted an Action Plan to fix the minimum agricultural tariff of 50 P/kwh.

नाथपा झाकरी में पन बिजली परियोजना

995. **श्री शांति त्यागी :** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नाथपा झाकरी में 1500 मेगावाट क्षमता वाली पन-बिजली परियोजना को अपनी मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की सम्भावना है और यह योजना कब तक पूरी कर ली जाएगी, और

(ग) इस परियोजगा के पूरा होने पर विद्युत का वार्षिक उत्पादन कितना होगा और बाद में इसका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) (क) और (ख) भारत सरकार ने 4337.95 करोड़ रुपए की अनुमानित लागतों वाली नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना (6X250= 1500 मे०वा०) के लिए अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस परियोजना को दिसम्बर, 1998 तक चालू कर दिए जाने की प्रत्याशा है ।

(ग) इस परियोजना से 90% विश्वसनीय वर्ष में 6700 मिलियन यूनिट वैद्युत ऊर्जा का उत्पादन किए जाने की प्रत्याशा की गई है जिसमें से 1500 मेगावाट व्यस्ततमकालीन विद्युत उत्तरी क्षेत्र को उपलब्ध कराई जाएगी । इससे कालान्तर में पर्यावरण पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यह परियोजना एक सरित-प्रवाही स्कीम है जिसके अन्तर्गत केवल 60 मीटर ऊंचे विपथन बांध का निर्माण किया जाना है जिससे किसी प्रकार का जल अवरोध नहीं होगा । तद्नुसार, पारिस्थितिकी, जनसंख्या का विस्थापन तथा वनों की कटाई संबंधी समस्यायें बहुत ही कम होने की प्रत्याशा है ।

उत्तर प्रदेश में विद्युत संकट

996. **श्री शांति त्यागी** क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में विद्युत संकट का प्रमुख कारण अनपारा-बी और अनपारा-ए के विद्युत गृहों का चालू न होना है ;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने कुछ सप्ताह पूर्व केन्द्रीय सरकार का ध्यान इन दोनों विद्युत गृहों को शीघ्र चालू कराने और अनपारा-उन्नाव तथा अन.पारा-गोरखपुर की ट्रांसमिशन लाइनों के बिछाने की ओर दिलाया था; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) से (ग) अनपारा "क" (3X210 मे०वा०

संतोषजनक ढंग से प्रचालन कर रहा है। अनपारा "ख" में 500-500 मेगावाट की दो यूनिटों की परिकल्पना की गई है। इसकी पहली यूनिट को समकालित किए जाने सम्बन्धी सभी परीक्षण कार्य 19-7-93 तक पूरे कर लिए गए हैं। दूसरी यूनिट को चालू वर्ष (1993-94) के दौरान चालू कर दिए जाने की प्रत्याशा है। उत्तर प्रदेश में बिजली की कमी होने के मुख्य कारणों में कुछ ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा असंतोषजनक कार्य निष्पादन तथा अधिष्ठापित क्षमता में कमी होने शामिल था।

योजना आयोग द्वारा अनपारा-उन्नाव 800 के०वी० पारेषण लाइन को अनपारा "ख" (2X500 मे० वा०) ताप विद्युत एक भाग के केन्द्र से सम्बद्ध पारेषण प्रणाली के एक रूप में सिद्धांत रूप में अप्रैल, 1989 में अनुमोदन प्रदान किया गया। इस लाइन के लिए वन सम्बन्धी स्वीकृति प्राप्त हो जाने के पश्चात् अतिशीघ्र ही इस लाइन पर कार्य आरंभ किए जाने की प्रत्याशा की गई है। अनपारा तथा गोरखपुर के बीच पारेषण लाइन का निर्माण किए जाने के संबंध में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 400 के.वी. गोरखपुर-आजमगढ़ पारेषण लाइन के निर्माण कार्यों को उ०प्र०रा०वि० बोर्ड की पारेषण प्रणाली के एक अंग के रूप में पहले ही अनुमोदन दे दिया गया है।

उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं पर सरकार द्वारा व्यापक रूप से निगरानी

997. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं को पूर्ण रूप से लागू करने के लिए उन पर व्यापक रूप से निगरानी रख रही है।

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(ग) सरकार को इसमें कितनी सफलता मिली है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगया नायडू) : (क) से (ग) जी, हां। उत्तर प्रदेश में विद्युत परियोजनाओं के कार्यान्वयन सम्बन्धी स्थिति की सरकार द्वारा सघन रूप से मानीटरिंग की जा रही है। निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय पर पूरा किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना प्राधिकारियों आदि के साथ आवधिक रूप से बैठकें की जाती हैं और विभिन्न समस्याओं को हल किया जाता है।

परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों में से एक निधियों की कमी होना है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं को सतत रूप से विदेशी सहायता हेतु प्रस्तुत किया जाता रहा है। विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रभावी रूप से प्रोतसाहित किए जाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

Power position in Gujarat

998. SHRI RAJUBHAI A. PARMAR: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) what is the existing installed capacity of power generation in Gujarat;

(b) what is the Plant Load factor in Gujarat and the average of national Plan Load factor during 1992-93; and

(c) what efforts have been made or are proposed to be made to bring the power generation capacity of Gujarat at the national level?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) The present installed generating capacity of the existing power stations in State of Gujarat is 5641 MW.

(b) During the year 1992-93 the plant load factor (PLF) of theremal power stations in Gujarat was 61.7 per cent as against the National average PLF of 57.1 per cent.